

खनन हेतु रॉयल्टी दरों को कैबिनेट की स्वीकृति

प्रलिस के लयि:

कैबिनेट द्वारा खनन हेतु रॉयल्टी दरों को स्वीकृति, [खान और खनजि \(वकिस तथा वनियिमन\) अधनियिम, 1957 \('MMDR Act'\)](#), लथियिम और नाइओबयिम, [खान और खनजि \(वकिस तथा वनियिमन\) संशोधन अधनियिम, 2023](#), दुर्लभ पृथ्वी धातुओं ।

मेन्स के लयि:

कैबिनेट द्वारा खनन हेतु रॉयल्टी दरों को स्वीकृति, वशिव भर (दक्षणि एशया और भारतीय उपमहाद्वीप सहति) में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वतिरण

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 [महतत्वपूरण और रणनीतिक खनजिओं](#) अर्थात् लथियिम, नाइओबयिम एवं [दुर्लभ मृदा तत्व \(REE\)](#) के संबंध में रॉयल्टी की दर नरिदषिट करने के लयि [खान और खनजि \(वकिस तथा वनियिमन\) अधनियिम, 1957 \('MMDR अधनियिम'\)](#) की [दूसरी अनुसूची](#) में संशोधन को मंजूरी दे दी है ।

- इससे केंद्र सरकार देश में पहली बार लथियिम, नाइओबयिम और REE के लयि ब्लॉकों की नीलामी कर सकेगी ।

नोट:

- [खान और खनजि \(वकिस तथा वनियिमन\) संशोधन अधनियिम, 2023](#) संसद द्वारा पारति कया गया, जो 17 अगस्त, 2023 से लागू हुआ ।
- संशोधन ने लथियिम और नाइओबयिम सहति छह खनजिओं को परमाणु खनजिओं की सूची से हटा दिया, जसिसे नीलामी के माध्यम से नजि क्षेत्र कोइन खनजिओं के लयि रयायतें देने की अनुमति मिलि गई ।

रॉयल्टी दरें:

- परचिय:**
 - खनजि रॉयल्टी वह भुगतान है जो सरकार को खनजि संसाधनों के नषिकरण की अनुमति देने के लयि **प्राप्त होती है** ।
 - सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (CSEP)** की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वशिव में भारत की खनजि रॉयल्टी दरें सबसे अधिक हैं, जो इसके खनन क्षेत्र की प्रतसिपर्द्धात्मकता को प्रभावति करती हैं ।
- प्रमुख संशोधन:**
 - MMDR अधनियिम** की **दूसरी अनुसूची** वभिनिन खनजिओं के लयि रॉयल्टी दरों का प्रावधान करती है । संशोधन से इन खनजिओं के लयि रॉयल्टी दरें काफी कम हो गई हैं ।
 - उदाहरण के लयि लथियिम खनन पर **लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य के आधार पर 3% की रॉयल्टी** लगेगी ।
 - नाइओबयिम भी, प्राथमिक और द्वतीयक दोनों स्रोतों के मामले में, ASP पर गणना की गई 3% रॉयल्टी के अधीन होगा ।
 - REE में **रेयर अर्थ ऑक्साइड** (वह अयस्क जसिमें REE सबसे अधिक पाया जाता है) के **ASP (औसत बिक्री मूल्य) के आधार पर 1% की रॉयल्टी** होगी ।
 - खान मंत्रालय ने इन खनजिओं के ASP की गणना करने का तरीका नरिधारति कया है, जसिके आधार **पखडि (bid) पैरामीटर नरिधारति कयि जाएंगे** ।
 - आयात को कम करने तथा **इलेक्टरिक वाहन (EV)** और ऊर्जा भंडारण समाधान जैसे संबंधति अंतमि-उपयोग (end-use) उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से घरेलू खनन को बढ़ावा देने की मांग की गई है ।

प्रयास का महत्त्व:

- नज़ी क्षेत्र की भागीदारी:
 - चूँकि सरकार ने इन खनजिों को "नरिदषिट" परमाणु खनजिों की सूची से हटा दिया है, इसलिये यह संशोधन नज़ी क्षेत्र के लिये नीलामी रियायतों के माध्यम से भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करता है।
- ग्लोबल बेंचमार्कगि और व्यावसायिकि दोहन:
 - वैश्विकि मानकों के अनुरूप नई रॉयल्टी दरों को नरिदषिट कर, सरकार केंद्र सरकार अथवा राज्यों द्वारा आयोजित प्रतस्पर्धी नीलामयिों के माध्यम से इन खनजिों के व्यावसायिकि दोहन को बढ़ावा दे रही है।
- घरेलू खनन और उद्योगों को बढ़ावा देना:
 - इस प्रयास का उद्देश्य आयात को कम करने के लिये घरेलू खनन को प्रोत्साहित करना तथा इलेक्ट्रिकि वाहनों व ऊर्जा भंडारण समाधान जैसे अंतमि-उपयोग उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है।
- शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्ति:
 - इस संशोधन में लक्ष्यित महत्त्वपूर्ण खनजिों को भारत के ऊर्जा परिवर्तन तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के लिये आवश्यक माना जाता है।
- चीन के वरिद्ध रणनीतिकि प्रयास:
 - लथियम-आयन ऊर्जा भंडारण वस्तुओं के एक प्रमुख उत्पादक चीन पर अपनी नरिभरता कम करने के लिये भारत लथियम मूल्य शृंखला में शामिल होने का प्रयास कर रहा है।

लथियम, REE, नाइओबियम से संबंधित मुख्य बदि:

- लथियम:
 - इलेक्ट्रिकि वाहनों, लैपटॉप और मोबाइल फोन में उपयोग की जाने वाली रचिरजेबल लथियम-आयन बैटरी के लिये लथियम एक मुख्य घटक है। वर्तमान में भारत लथियम के लिये आयात पर नरिभर है तथा इसने हाल ही के वर्षों में लथियम नषिकर्षण के लिये जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अन्वेषण प्रयास किये हैं।
- दुरलभ मृदा तत्त्व (REE):
 - इलेक्ट्रिकि वाहनों में प्रयुक्त स्थायी चुंबक मोटरों के लिये REE अत्यावश्यक हैं। ये मुख्य रूप से चीन से प्राप्त अथवा संसाधित होते हैं, जो भारत की आपूर्ति शृंखला की चुनौती को दर्शाता है।
 - दुरलभ पृथ्वी तत्त्वों (REE) के खनन से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत पर्यावरणीय संधारणीयता को ध्यान में रखते हुए REE की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कार्य कर रहा है।
- नाइओबियम:
 - नाइओबियम का उपयोग मशिर धातुओं (alloys) को और मज़बूत करने के लिये कया जाता है, जो उन्हें जेट इंजन, इमारतों, तेल एवं गैस पाइपलाइनों, MRI स्कैनर के लिये मैग्नेट आदि जैसे वभिन्न अनुप्रयोगों में विशेष रूप से उपयोगी बनाता है।
 - नाइओबियम एक चांदी जैसी धातु है जो अपनी सतह पर ऑक्साइड की परत के कारण संक्षारण के प्रति अत्यधिक प्रतिरिधी है।
 - नाइओबियम चाँदी जैसी दखिने वाली एक धातु है जिसकी सतह पर ऑक्साइड की परत मौजूद होती है जो इसे अत्यधिक संक्षारण रोधी बनाती है।

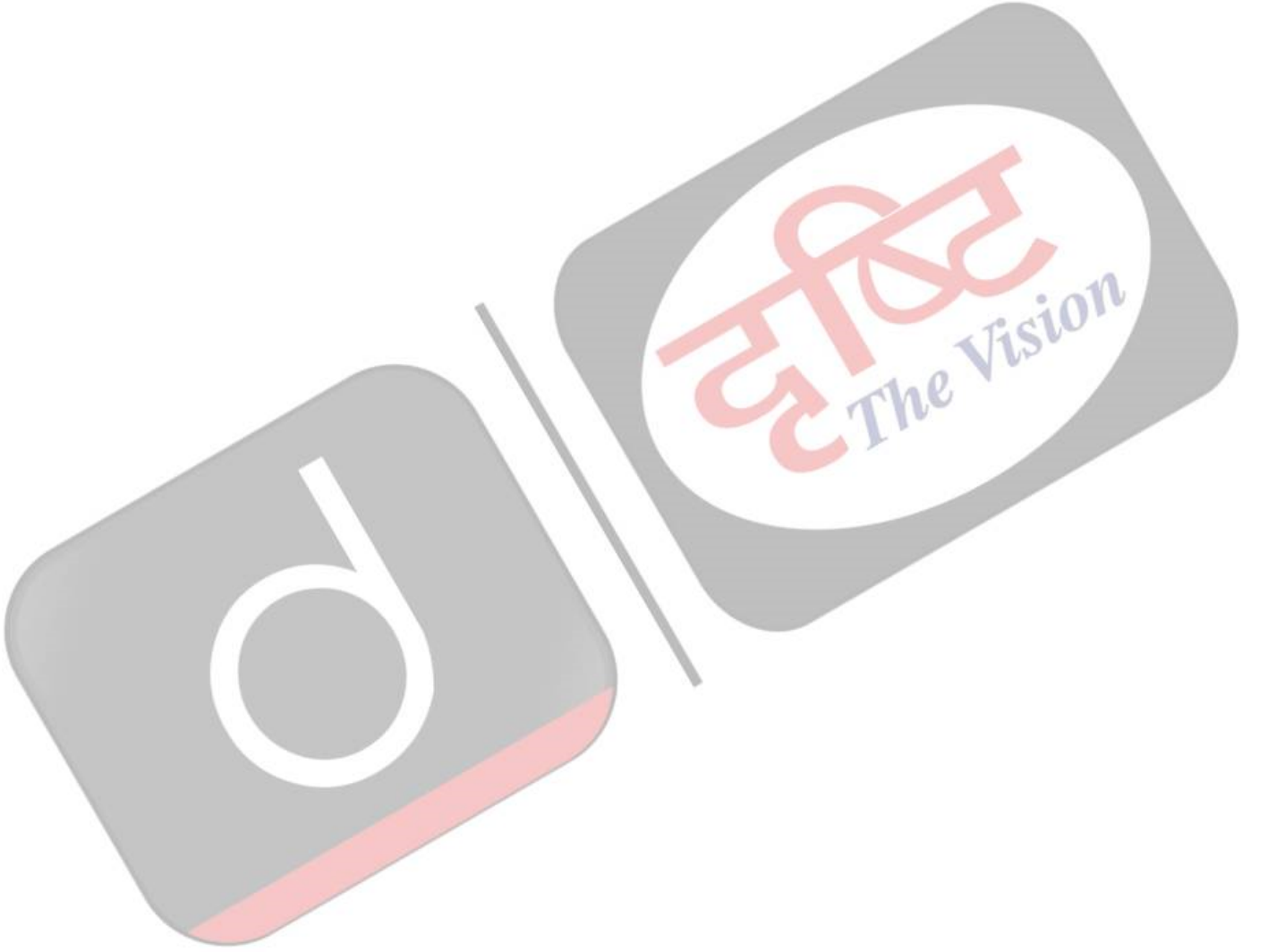
भारत में खनन क्षेत्र का परदृश्य:

- वनिरिमाण क्षेत्र की रीढ़:
 - खनन उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है, यह वनिरिमाण और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों के लिये रीढ़ की हड्डी अर्थात् प्रमुख आधार के रूप में कार्य करता है।
 - खनन और उत्खनन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.5% का योगदान है।
- वसितार:
 - लौह अयस्क उत्पादन के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है और आँकड़ों के अनुसार, विश्वभर में कोयला उत्पादन के संदर्भ में भारत वर्ष 2021 में दूसरे स्थान पर था।
 - संयुक्त रूप से वरिष्ठ वर्ष 2021 में 4.1 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एल्युमीनियम उत्पादन (प्राथमिकि और द्वितीयक) के साथ भारत विश्वभर में दूसरे स्थान पर था।
 - विश्व खनजि उत्पादन 2016-20, ब्रिटिश भू-वैज्ञानिकि सर्वेक्षण के अनुसार, उत्पादन मात्रा के संदर्भ में विश्व में वर्ष 2020 में उत्पादन में भारत की रैंकगि:

खनजि/संसाधन	वर्ष 2020 में उत्पादन में रैंक
कोयला एवं लग्निाइट	2 nd
स्टील (कच्चा/तरल)	2 nd

जस्ता (स्लैब)	3 rd
एल्यूमीनियम (प्राथमिक)	3 rd
क्रोमाइट अयस्क एवं सांद्रण	4 th
लौह अयस्क	4 th
ग्रेफाइट	4 th
मैंगनीज अयस्क	5 th
बाक्साइट	6 th
तांबा (परष्कृत)	7 th

- वर्ष 2023 में भारत में वदियुतीकरण के वस्तितार और समग्र आर्थिक विकास के कारण खनजि की मांग में 3% की वृद्धि होने की संभावना है ।
 - भारत को इस्पात और एल्यूमिना के उत्पादन और रूपांतरण से काफी लाभ होता है । इसका प्रमुख कारण इसकी रणनीतिक अवस्थिति है जो नरियात क्षमता के विकास के साथ-साथ एशियाई बाजारों में तेज़ी से विकसित होने में मदद करती है ।



METALS AND MINING



MARKET SIZE

Trend Point: GVA from mining and quarrying stood at US\$ 43.3 billion in FY22, as per the advance estimates.

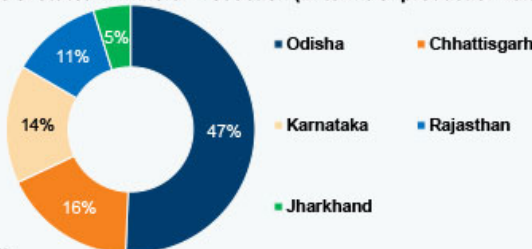


Note: RE- Second Revised Estimate ; GVA - Gross Value Added



SECTOR COMPOSITION

Share of States In Mineral Production (in terms of production value, FY22E)



Note: E- Estimate



KEY TRENDS

Mineral Production in India (in US\$ billion)^



Note: ^Excluding atomic and fuel minerals, P- Provisional, E- Estimate



GOVERNMENT INITIATIVES



ADVANTAGE INDIA

- Demand growth:** In 2023, the mineral's demand is likely to increase by 3%, driven by expanded electrification and overall economic growth in India.
- Attractive opportunities:** Under PLI Scheme for Specialty Steel, 67 applications from 30 companies have been selected that will attract committed investment of Rs. 42,500 Crore (US\$ 5.1 billion) with a downstream capacity addition of 26 million tonne and employment generation potential of 70,000.
- Policy support:** Enactment of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 enabled captive mines owners (other than atomic minerals) to sell up to 50% of their annual mineral (including coal) production in the open market.
- Competitive advantage:** India holds a fair advantage in cost of production and conversion costs in steel and alumina. As of FY22, the number of reporting mines in India were estimated at 1,245, of which reporting mines for metallic minerals were estimated at 525 and non-metallic minerals at 720.

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. गॉडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बहुत कम प्रतिशत योगदान है। चर्चा कीजिये। (2021)

प्रश्न. प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिये अभी भी अपरहिर्य है"। वविचना कीजिये। (2017)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-royalty-rates-for-mining>

